''भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ और बातें''

भ्रष्टाचार भारत का बातचीत का पसंदीदा विषय है। हम चाव से इसकी चर्चा करते हैं और इसकी व्यापकता का रोना रोते हैं। जब भी दो या अधिक भारतीय मिलते हैं तो बातचीत का क्रम अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार की ओर मुड़ जाता है। कभी–कभी मैं आश्चर्य करता हूँ कि यदि यहाँ भ्रष्टाचार का विषय नहीं होता तो हम एक–दूसरे से क्या बातें करते? लगभग हम सब इसके विशेषज्ञ हैं और इसके सभी स्तरों एवं रूपों के पूरे अनुभवी हैं। लेकिन इतने सारे साझे अनुभव के बाद भी यह ऐसा विषय है जिस पर नहीं के बराबर लिखा जाता है। हमारे करोड़ों भगवानों की तरह भ्रष्टाचार के भी असंख्य रूप हैं। इसे साधारण परिभाषा में बांधा जा सकता हे पर हम सभी जानते हैं कि यह क्या चीज है। जैसा कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पॉटर स्टीवर्ट अश्लीलता के संदर्भ में कहते हैं– ''मैं इसे जानता हूँ पर तभी जब इसे देखता हूँ।'' यह बात समान रूप से भ्रष्टाचार पर लागू होता है और हमारे समाज के अधिकांश लोगों की प्रतिज्ञाओं को देखते हुए यह अश्लीलता से भी अधिक अश्लील लगती है जिसे बेशक हम तभी जानते हैं जब देखते हैं। भ्रष्टाचार सार्वजनिक है और हम जानते हें कि यह क्या है।

अर्थशास्त्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग ढंग से बात करते हैं वे इसे 'आर्थिक भार' कहते हैं। आई.एम.एफ. के अनुसार ''यह अतिरिक्त मात्रा का भुगतान (सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग के लिए जो भी किया जाए) है जो किसी व्यक्ति के लिए होता है अथवा किसी ऐसे उपयोगी वस्तु से संबंधित होता है जिसकी आपूर्ति प्राकृतिक कारणों या मानवीय चालाकी के कारण सीमित होती है।'' बिल्कुल साफ है कि यह परिभाषा नैतिकता के पक्ष को दरकिनार करती है। पर, तब हमारी समस्याएँ और जटिल हो जाती हैं जब हमें पता चलता हे कि नैतिकता अपने आप में ही एक अत्यंत लचीली और परिवर्तनशील है जो समय, स्थान और संदर्भ पर निर्भर करती है।

उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मामले को लेते हैं, वे हमारे उन गिने चुने प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन जहाँ तक राज्य सभा का मामला है, वह श्री हितेश्वर

साकिया के किरायेदार रहे हैं और आसाम के गुवाहाटी के निवासी रहे हैं। हम जानते हैं कि यह सच नहीं हे। जब से हम उन्हें जानते हैं वे दिल्ली के ही सामान्य निवासी रहे हैं। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवानी लगभग भ्रमणशील रहे हैं। एक समय राज्यसभा की सीट के लिए उन्होंने घोषणा की कि वे मध्यप्रदेश में उज्जैन के निवासी हैं। यही नहीं, अधिकारिक रूप से अनिवासी भारतीय होने के बावजूद अनिल अम्बानी उत्तर प्रदेश के और विजय माल्या कर्नाटक के निवासी हैं। लेकिन अगर आप और हम तथ्यों के मामले में ऐसा लचीलापन या लापरवाही बरतें और अपने निवास स्थान के बारे में पासपोर्ट के लिए ऐसी सूचनाएँ दें तो हमें जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

आर्थिक भार दूसरे रूप में भी ग्रहण करता है, यह सामान्य वस्तुओं पर अधिक कर के रूप में आता है। उदाहरण के लिए उच्च आयात शुल्क का मतलब वास्तव में घरेलू निर्माताओं के मूल्यों और लाभों में वृद्धि के लिए आयात को नियंत्रित करना है। हिन्दुस्तान की अम्बेसडर कार ने जो बुद्धिहीन और लालची प्रशासन का अमर प्रतीक है वास्तव में अपने निर्माताओं और कर्मचारियों को जितनी खुशी दी है इन कार के चालकों और मालिकों को उतनी ही पीड़ा दी है। क्या आपने गौर किया है कि कैसे सभी कार टायरों और बैक्ट्रियों का दाम एक बराबर होता है? या कैसे सभी समान आकार वाले वातानुकूलित यंत्रों और फ्रीजों का मूल्य बराबर है? या कैसे अभी हाल तक सभी हवाई टिकटों के मूल्यों में इतनी समानता और समान रूप से इतना ऊँचा मूल्य कैसे रहा हद्वै। एडम स्थिम इसे समझते हुए बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि, ''समान व्यापार करने वाले लोग कभी–कभार ही साथ बैठते हैं, जैसे मौज–मस्ती या मनबहलाव के लिए, लेकिन इनकी बातचीत का अंत जनता के विरुद्ध षड्यंत्र में होता है।''

इन षड्यंत्रों की सफलता राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की सक्रिय सहमति के बिना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि अधिकांशतः वे क्या करते हैं, लेकिन अनिरुद्ध बहल के प्रयासों का धन्यवाद जो एक उद्योग संगठन के प्रतिनिधि का दाव कर रहे हैं और जिनके कारण हमारे पास पहली बार इसके प्रमाण हैं। हमारे सांसदों ने एम.

पी. लैंड्स (सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) के जादू के लिए प्रधानमंत्री को काफी धन्यवाद दिया है, लेकिन तब वित्त मंत्री ने संभवतः आदरणी साक्षी महाराज की पसंद के बारे में कभी नहीं सोचा होगा जिन्होंने व्यक्तिगत विकास के लिए योजना को ही मोड़ दिया। दोनों स्टिंग्स जो सांसदों के घोटालों की वीडियो रिकार्डिंग में शामिल हैं, इन दोनों में जमीन–आसमान का फर्क है। प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने का काम आम है जैसे ट्रैफिक पुलिस गुमराह चालकों से पैसे ऐंठती है। यह भुगतान अपने आप में कर्त्तव्य–विमुख होने का दंड है और यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता कि अंत में रुपये का भुगतान कहाँ होता है। हम इससे अपनी वास्तविकता समझते हैं। लेकिन जब पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए या बिना किसी कारण के ही पैसा ऐंठती है तब यह दूसरी बात होती है और तब हम सचमुच सताए जाते हें। मेरा मानना है कि जो सांसद कागजों पर हस्ताक्षर कर सवाल पूछले के लिए उपहार लेते हैं उनके साथ वही बरताव नहीं होना चाहिए जो कि एम.पी. लैंड्स से कटौती की मांग करने वाले सांसदों के साथ हो रहा है। प्रश्न पूछने वाले आर्थिक भार वसूल रहे थे और उसमें राज्य का कोई नुकसान नहीं हो रहा था जबकि एम.पी. लैंड्स के लोग सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आर्थिक क्षति का षड्यंत्र कर रहे थे।

बेहल स्टिंग का तीव्र संवेदी कैमरे का कार्य जिसने वीडियो रूप में आँखों की लालची चमक और रुपयों की स्फूर्तिदायक कुरमुरेपन को कैद किया है उसने सजीव नाटक प्रस्तुत किया। और जब कैमरे ने दीवार पर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गुरु गोलवलकर के चित्र को प्रदर्शित किया तो दृश्य पूरी तरह नाटकीय था। अनिरुद्ध का यह पहला स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, यह फिल्म देखकर प्रमाणित हो जाता है। लेकिन हमारा संसद सत्यनिष्ठा का ऐसा ऊँचा प्रतिमान रखता है कि तुलनात्मक रूप से छोटा अपराध भी इसकी पवित्रता में बट्टा लगाता प्रतीत होता है और इसलिए उन्हें निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। बेशक सांसदों ने बाइबिल का यह उपदेश नहीं सुना, ''तुममे से पहला पत्थर वह मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया।'' यहाँ तक सउदी कंगारू न्यायालय ने भी बेहतर काम किया होता। कभी–कभी कुछ काम सिर्फ इसलिए अक्षम्य हो जाते हैं क्योंकि वे सार्वजनिक स्थलों

पर किए गए होते हैं। हममें से जिन्होंने दिल्ली में यह जानते हुए भी कि यह नियम विरुद्ध है, संस्था के अनुमोदन के बगैर अतिरिक्त निर्माण हेतु पैसे दिए हैं या घर बनाए हैं उन्हें यह पता है कि यह गैर–कानूनी है। लेकिन यह आम बात थी और शायद इसी कारण यह सही–सलामत रह गया। अब जब उच्च न्यायालय ने उन भवनों को तोड़ने का आदेश दे दिया है तो हमें यह अन्यायपूर्ण लगता है। इससे क्या होता है कि उसी न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि अपने निवास स्थान के बारे में गलत जानकारी देने वाले नेता मुक्त कर दिये जाएँ। क्या यह हम पर अत्याचार होगा? हम खुश हो सकते हैं लेकिन पीड़ित नहीं। साफ तौर पर यह एक ऐसा विषय है जिस पर वृहत स्तर पर चिन्तन और बहस की जरूरत है और यहाँ संसद आत्मनिरीक्षण करके बहुत कुछ कर सकती है। ऐसे बहुत से लोग है जिनको इस विषय में महारत हासिल है। भाजपा के चंदन मित्रा जो कि ईमानदारी के लिए विख्यात हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर एक किताब तक लिख चुके हैं।

बहुमत बताता है कि यहाँ कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें हम पूर्णतः भ्रष्ट मानते हैं। इस सूची में राजनीतिज्ञ और पुलिस सबसे ऊपर है जिनमें 99 प्रतिशत लोग मतदान के अनुसार धूर्त हैं। हमारे रोजमर्रा जीवन में दिखाई पड़ने वाले अधिकतर भ्रष्टाचार उनके अनावश्यक प्रयासों के परिणाम हैं। पिछले कुछ महीनों से मुझे हर सुबह पड़ोस के एक खाली जमीन का अवलोकन करने का अवसर मिलता रहा है। सड़कें उस जगह को चारो तरफ से घेरे हुए हैं और स्वभावतः पैदल जाने वाले लोगों ने इसे संक्षिप्त मार्ग बना लिया है। अनुशासन को पसन्द करने कवाले कुछ लोगों ने इस कार्य को बन्द करने का बीड़ा उठाया। पहले एक संकेत आया जिसमें मांग उठायी गयी थी कि लोग शार्ट कट लेने के लिए बुद्धिवादी कार्य कर रहे हैं, ऐसा न करें। संकेत को अनदेखा कर दिया गया और मेरा कुत्ता चार्ली मार्गपट्ट को अपने दस्तखत के लिए इस्तेमाल करता रहा है। फिर दो खम्भों के बीच एक छोटा सा कँटीला तार बाँध दिया गया। जो लोग उस मार्ग का उपयोग करते हैं वे अब भी उतना शार्ट–कट न लेकर खम्भे के पास से घूम जाना आरामदायक समझते हैं।

समझदार चार्ली तार के नीचे से निकल लेता है और काफी प्रसन्न मालूम होता है कि उसके पास प्रति दिन का चिह्न छोड़ने के लिए दो और खम्भे हैं।

हमारे अधिकांश नियमों (निर्देशों) की प्रकृति बिल्कुल ऐसी ही है। वे अविवेकी हैं और हम अगर उन्हें अनदेखा न करें तो उनको धोखा देकर विवेकपूर्ण जबान देंगे। ठीक जैसा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने इस माँग के साथ किया था कि उच्च सदन के सांसदों को सामान्यतः राज्य में निवास करना चाहिए। अब भूमि खण्ड को शार्ट–कट के प्रयोग से बचाने का एक ही उपाय है कि इसपर निर्माण कर दिया जाए। अगर खाली जमीन पर केवल दीवार भी खड़ी कर दी जाए तो, दीवारों से अन्य उपयोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो जूतों के लिए कष्टकारी होगा। जो नियम सामान्य अनुभव से संघर्ष करते हैं वो सफल नहीं होतें जो मुझे दूसरे पहलू पर लाता है। हमारे यहाँ नियम हैं जो सार्वजनिक जगहों पर, दीवारों पर और निजी जगहों पर पेशाब करने से मना करते हैं। पेशाब करना एक निजी कार्य है। लेकिन जब आपके पास पर्याप्त पेशाब घर नहीं है तो लोग कहाँ पेशाब करेंगे? अतः सार्वजनिक जगहों पर मूत्र त्यागने के विरुद्ध नियम का पालन तभी संभव है जब आपके पास पर्याप्त पेशाबघर हो।

विचारहीन नियम एक राज्य को पूर्णरूप से नष्ट करते हैं। यही कारण है कि राज्य द्वारा बनाए गये कठोर नियम–कानून और उच्च मानवीय आदर्शवाद की अपील असफल हो जाती है। अपराध का ज्वार जो कि पूर्व सोवियत रूस को निगल गया, वह वास्तव में प्राचीन नॉनेनक्लेटुरा के केवल एक ही चीज करने के कारण हुआ जिसमें वे निपुण थे।

ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे सामाजिक, राजनीतिक तंत्र भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देते हैं। भ्रष्टाचार एक पूर्ण व्यापक एवं विश्वस्तरीय घटना है। इसका उदय प्रकृति के साथ ही होता है।

पशु ठीक उसी तरह एक–दूसरे का भोजन चुराते हैं जैसे कि मनुष्य दूसरों से छीनते हैं। लेकिन मानव संगठित समाज में रहता है और समाज एक नियम के आधार पर बने तंत्र के अलावा कुछ नहीं है। नियम को लागू होने के लिए यह

बिल्कुल साथ होना चाहिए कि यदि पकड़े जाते हैं तो जाँच तेजी से होगी और यदि दोषी पाये जाते हैं तो अनुपातिक रूप से दण्ड दिया जाएगा।

यही हमारी गम्भीर समस्या है। कौन नियम बनाता है? राजनीतिज्ञ। कौन नियम को बहाल करता है? पुलिस। दोनों ही अत्यधिक भ्रष्ट माने जाते हैं। और क्या हम न्यायपालिका से बेहतर कार्य की उम्मीद कर सकते हैं? उदाहरण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समित मुखर्जी को लेते हैं, जो न्याय का गला घोट कर सुविधा–जनक जगह की व्यवस्था करते हुए पकड़े गये। हमें खास तौर पर अरुण जेटली को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए । यहाँ इनकी तरह अनेक हैं जो न्यायापालिका की शोभा बढ़ाते हैं। क्या वे जज नैतिक उल्लंघन के दोषी नहीं हैं जो नामी–गिरामी निजी क्लबों की सहायता ग्रहण करते हैं? और हमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने जैन शुद्ध वनस्पति मामलों में जल्दी से अनुकूल निर्देश जारी कर दिया था।

वर्तमान एवं अपेक्षाकृत ईमानदार समाज के ऐसे तंत्र की जरूरत है जो तीव्र गति से कार्य करे और उल्लंघन करने वालों को आनुपातिक रूप से दण्ड दे। यह स्पष्ट है कि हमारे पास साफतौर पर ऐसा नहीं है और भविष्य में यह हो भी नहीं पाएगा। एक ही रास्ता है, जिससे हम उसे अपने लिए पा सकते हैं, वह है जागरूक मीडिया जो कि कठोरता पूर्वक जाँच करता है और पर्दाफाश करता है। अनिरुध बहल दुर्भाग्य रूप से अभी भी अल्पसंख्यक हैं। वो सहर्मी जो अभी भी मीडिया व्यवसाय को संचालित करते हैं वे वही लोग हैं, जिन्होंने मीडिया को एक व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया है, जैसाकि महरौली में कर्मियों ने अपने लिए फार्म हाउस प्राप्त कर लिया। या वे लोग जो लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के भत्ता सूची में पाए गए। तब यह लोगों को अपना बचाव स्वयं करने पर विवश करता है। जो कि वे भारत के उग्रवाद प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं।

Mohan Guruswamy
Email : mguru@sify.com
December 23, 2005